सभी प्रकार की सरकारी सहायताओं से मुक्त, खोजी पत्रकारिता का तेज बढ़ता अखबार

दैनिक

themovementofindia.in

द मूवमेंट ऑफ़ इंडिया

RNI No. RAJHIN/2012/48876
पोस्टल पंजीयन नं. भीलवाड़ा / 2025-2027

खोजी खबरें-तेज नजरें

प्रेरणा स्रोत - स्व. चुन्नीलाल सालवी

ये अखबार ही नहीं क्रांति का अभियान है। मानवता एवं लोकतंत्र का सजग प्रहरी, ये दुष्टों की मौत का सामान है।

वर्ष - 14 अंक -29 | 24 जुलाई 2025,गुरुवार | संपादक - दयाराम दिव्य | सहसंपादक - चाहत सालवी | मूल्य - 2 रू.

बिजयनगर का हिस्ट्रीशीटर सूर्या गिरफ्तार

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा की पुर थाना पुलिस थाना ने डीएसटी से मिले के इनपुट के बाद HBS गैंग के मेंबर और बिजयनगर थाने के हिस्ट्रीशीटर सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर को गिरफ्तार किया।

पुर थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि सूचना मिली कि पुलिस थाना माण्डल का हिस्ट्रीशीटर और HBS गैंग के मुखिया गोपाल लाल गुर्जर निवासी जिपिया खेड़ी थाना माण्डल भीलवाडा ने अपने जन्मदिन के मौके पर में हा॥-48 पर स्थित पालना देवनारायण मन्दिर के परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया है। जिसमें आमजन की आड़ में विभिन्न जिलों से HBS गैंग के मेंबर, संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को बुलाया गया। इस पर पुलिस की टीम पालना देवनारायण मन्दिर पर पहुंची, जहां मन्दिर के सामने हाईवे पर करीब 700-800 लोगों की भीड़ और मन्दिर परिसर में 10-12 हजार लोगों को भीड़ इकट्ठी होकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।

इनके खिलाफ मामले दर्ज

पुलिस ने आयोजनकर्ता गोपाल लाल पुत्र कानाराम गुर्जर निवासी जिपिया खेड़र, छोटू बगडावत पुत्र शंकर बगडावत जिपियाखेडी, नारू लाल पुत्र दुर्गालाल बंजारा कृषि मण्डी के सामने भीलवाड़ा, सत्यनारायण उर्फ सत्तू पुत्र बद्रीलाल बजाड निवासी बजाडो का खेडा रायला, सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर पुत्र घनश्याम गुर्जर विजयनगर, गोविन्द गुर्जर जवाहरनगर भीलवाड़ा, हरफूल गाडरी सुरास, देवराज गुर्जर ठगों का खेडा, हंसराज अठारिया पुर, पवन साहू यूट्यूबर, सुखदेव गुर्जर बर ब्यावर, सिंगर माया गुर्जर, सिंगर राजू रावल। योगेश गुरू यूट्यूबर, मुकेश गुर्जर जिपिया खेड़ी, कमलेश सुवालका निवासी आवरी माता, महावीर तेली आरजिया, पारस गुर्जर जालमपुरा, शैतान भडाना करमडास, फकरुद्दीन पुत्र शब्बीर खान भदालीखेडा, राजू खटाना देवसेना अध्यक्ष देवगढ़, मोनू वैष्णव करेडा हाल 200 फिट रोड, नियाज मोहम्मद धूलखेडा, श्रीलाल गुर्जर गुवारडी, नारायण भदाला जाट अगरपुरा, रतन राव सिंहाना, प्रेमशंकर जाट यूट्यूबर।

बिना परमिशन कार्यक्रम आयोजित किया

इन सबके द्वारा देर रात तक बिना परमिशन के सार्वजनिक आयोजन कर रात 10 बजे के बाद तक तेज आवाज में डीजे बजाना, लोकसेवक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना, लोकसेवक व पुलिस जाप्ता को राजकार्य करने से रोकना व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले दर्ज किए गए थे। घटना के बाद से ही सभी लोग से फरार होकर अपनी गिरफ्तार से बचने का प्रयास कर रहे थे।

20 से ज्यादा मामले दर्ज-बिजयनगर थाने का वांटेड

पुलिस ने इन्हे पकड़ने के बाद लिए विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने डीएसटी से मिले इनपुट के बाद बिजयनगर ब्यावर के हिस्ट्रीशीटर और ॥क्र गैंग के मेंबर सदस्य सुरेश उर्फ सूर्या पिता घनश्याम गुर्जर (29) निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बिजयनगर जिला ब्यावर को गिरफ्तार किया।आरोपी सुरेश के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार, एनडीपीएस एक्ट, अपहरण कर फिरोती मांगने, राजकार्य में बाधा आदि के करीब 20 से ज्यादा मामले दर्ज है। बिजयनगर के 2 मामलों में सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर वांटेड है।

गंभीर नदी में बहे पिता-पुत्र, बेटे का मिला शव

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

हिंडौन-गंगापुर मार्ग स्थित गंभीर नदी में बुधवार शाम 4 बजे पुल पार करने के दौरान बाइक सवार पिता-पुत्र बह गए। घटना की सूचना मिलने पर हिंडौन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश के लिए स्ठ्रक्र की टीम को बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गुरुवार सुबह 6 बजे पुलिया से लगभग 300 मीटर दूर बेटे का शव झाड़ियों में फंसा हुआ मिला है। वहीं स्ठ्रक्र की टीम पिता की तलाश में जुटी हुई है।

भैंस खरीदने के लिए जा रहे थे वजीरपुर

परिजनों ने बताया कि राजमुद्दीन और उसका बेटा सोहेल खान (20) बुधवार दोपहर 3:20 बजे दोनों भैंस खरीदने वजीरपुर जा रहे थे। इस दौरान कटकड़ की गंभीर नदी की पुलिया पार करते समय बाइक फिसल गई और दोनों नदी की गहराई में बह गए। जिसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

राजस्थान में बजरी, मार्बल और पत्थर महंगा हुआ:सेंड स्टोन पर 80 रुपए और बजरी पर 15 रुपए टन बढ़ोतरी

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

राजस्थान सरकार ने खनिज पदार्थों पर वसूल की जाने वाली रॉयल्टी शुल्क को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश में बजरी, पत्थर, मार्बल समेत कुल 24 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ाई गई है। रॉयल्टी बढ़ने का असर कंस्ट्रक्शन करवाने पर पड़ सकता है। नई अधिसूचना के मुताबि?क बजरी पर लगने वाली रॉल्यटी फीस को 15 रुपए प्रति टन, जबकि सेंड स्टोन (चेजा पत्थर) पर रॉयल्टी को 80 रुपए टन तक बढ़ा दिया है।

खनिज विभाग से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अभी तक भरतपुर, झुंझुनूं, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सीकर और भीलवाड़ा जिले से निकलने वाली बजरी पर रॉयल्टी 50 रुपए प्रति टन, जबकि शेष जिलों से निकलने वाली बजरी पर 45 रुपए प्रति टन की दर से वसूली जाती थी। अभी तक पूर्वी राजस्थान के इलाकों से निकलने वाली बजरी को अच्छी मानते हुए उन पर ज्यादा रॉयल्टी वसूली जाती थी, लेकिन सरकार ने अब सभी जिलों में समान दर पर रॉयल्टी लेने का नियम कर दिया। साथ ही इसे बढ़ाकर अब 60 रुपए प्रति टन कर दिया है।

जानकारों की मानें तो इस रॉयल्टी के बढ़ने से बजरी की कीमत प्रति ट्रक 600 रुपए तक बढ़ जाएगी। क्योंकि वर्तमान में एक ट्रक बजरी में अधिकतम 40 टन बजरी ले जाने की अनुमति रहती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चेजा पत्थर का कंस्ट्रक्शन में उपयोग होता है। इस पत्थर पर सरकार अभी तक 240 रुपए प्रतिटन रॉयल्टी वसूल करती थी। इसे अब बढ़ाकर 320 रुपए प्रति टन कर दिया है। यानी 80 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की है। ये रॉयल्टी तैयार पत्थर पर ली जाती है।

पोषाहार का मिल्क पाउडर घर ले जाते टीचर को पकड़ा:ग्रामीणों ने बैग खुलवाकर देखा तो घबरा गया

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा जिले में एक सरकारी स्कूल से मिल्क पाउडर ले जाते टीचर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उन्होंने टीचर का बैग खुलवाकर देखा तो उसमें मिल्क पाउडर की तीन थैलियां मिली। ग्रामीणों ने जब मिल्क पाउडर के बारे में पूछा तो टीचर घबरा गया और उनसे दूसरी स्कूल में सप्लाई करने के लिए कहा। मामला जहाजपुर क्षेत्र के जमोली पंचायत की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बदनपुरा का है। दरअसल, स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर करीब एक बजे टीचर सचिन टाक अपने बैग में मिल्क पाउडर की थैलियां डालकर ले जा रहा था। जब वह स्कूल से बाहर निकाला तो गांव के एक व्यक्ति ने उसे रुकवा लिया और उसका बैग चेक किया। बैग को चेक करने पर उसमें मिल्क पाउडर की तीन थैलियां मिली। इस दौरान वहां कुछ और ग्रामीण पहुंच गए। जब ग्रामीणों ने टीचर से मिल्क पाउडर स्कूल से बाहर ले जाने की पूछा तो वह घबरा गया। उसने दूसरी स्कूल में सप्लाई करने के लिए कहा। इस पर ग्रामीणों ने टीचर से लिखित में लेटर मांगा कि दूसरी स्कूल में सप्लाई के लिए ऑर्डर बताइए। आपके पास लिखित आदेश की कॉपी होगी उसे दिखाओ।

मामला बढ़ता देख टीचर सचिन टाक वापस स्कूल में चला गया और रूम का ताला खोलकर बैग अंदर रख दिया। टीचर सचिन टाक रूम से चेयर बाहर निकाल लाया और उस पर बैठ गया। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी बनाया है। स्कूल रूम में रखे बैग को खोलकर मिल्क पाउडर की थैलियां दिखाने की भी ग्रामीणों ने वीडियोग्राफी की। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बच्चे भी मौजूद थे।ग्रामीणों ने घटना की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की है। उन्होंने मांग की है कि टीचर यह मिल्क पाउडर कहां ले जा रहा था, इसकी जांच कराई जाए।

C M Y K

सम्पादकीय

स्वच्छ ऊर्जा में विश्व को राह दिखाता भारत

जलवायु परिवर्तन की निरंतर विकराल होती चुनौती के बीच स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने को लेकर कोई दुविधा नहीं। इसके बावजूद यह चर्चा जीवाश्म ईंधन और रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर अनावश्यक द्वंद्वों में फंसी है। इसमें ऊर्जा परिदृश्य पर संक्रमण की जटिलता को अनदेखा किया जा रहा है और यह स्थिति ग्लोबल साउथ यानी विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्था में अधिक देखने को मिल रही है। आवश्यकता जीवाश्म ईंधनों को पूरी तरह से त्यागने की नहीं, बल्कि उन पर निर्भरता घटाने की एक संतुलित नीति एवं गैर-जीवाश्म ईंधनों में रणनीतिक निवेश बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की है। सौर, पवन, जल, परमाणु और जैव ऊर्जा में निवेश इस रणनीति के मूल में होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि बीते एक दशक में सौर एवं पवन ऊर्जा की लागत 80 प्रतिशत से भी अधिक घट गई है। इसके चलते कई क्षेत्रों में सौर-पवन ऊर्जा की लागत कोयले और गैस से बनने वाली बिजली से भी किफायती हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा कीमतों में स्थायित्व प्रदान करने के साथ ही ऊर्जा स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है। एक बार इंस्टाल होने के बाद उसमें लागत लगभग नगण्य रह जाती है। ये कुछ ऐसे लाभ हैं जिनकी जीवाश्म ईंधन कभी बराबरी कर ही नहीं सकते। ऐसी क्षमताओं से भू-राजनीतिक गतिरोधों से भी सहजतापूर्वक निपटा जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में तनाव भड़कने से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका बड़ा उदाहरण रहा। स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में निवेश करने वाले देश ऐसी अस्थिरता से बचे रह सकते हैं।

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

महात्मा गांधी अस्पताल परिसर की धर्मशाला व कैंटीन संचालन पर उठे गंभीर सवाल

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा, दिनांक 23 जुलाई 2025 - राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में मरीजों की सुविधा हेतु निर्मित धर्मशाला एवं कैंटीन अब जनसेवा की जगह निजी लाभ का माध्यम बन चुकी हैं। इस गंभीर प्रकरण पर समाजसेवी एवं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के पूर्व सदस्य मोहम्मद हारून रंगरेज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्र जांच और सुधारात्मक कार्रवाई की माँग की है।

÷व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं, गरीबों के नाम पर कमाई÷ - हारून रंगरेज ज्ञापन में बताया गया कि श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला का मकसद था कि दूर-दराज़ से आने वाले मरीजों के परिजनों को राहत मिल सके, लेकिन अब वहां होटल जैसी दरें वसूली जा रही हैं, जिससे असहाय और गरीब मरीजों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

रिकॉर्ड नदारद, आय-व्यय पर सवाल

मोहम्मद हारून रंगरेज ने आरोप लगाया कि धर्मशाला में ठहरने वालों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, और वसूली गई राशि का कोई पारदर्शी लेखाजोखा नहीं है। यह सब कुछ नियमों और नैतिकता के विरुद्ध है।

कैंटीन का ठेका, गरीबों का नुकसान ज्ञापन में यह भी बताया गया कि धर्मशाला परिसर में संचालित कैंटीन का ठेका ?70,000 प्रतिमाह में निजी पक्ष को दिया गया है, जबकि सरकारी अस्पताल की कैंटीन महीनों से बंद पड़ी है, जिससे गरीब मरीजों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है।

÷सरकारी ज़मीन, निजी कब्जा?÷

धर्मशाला और कैंटीन सरकारी अस्पताल की भूमि पर बनी हैं, पर अस्पताल या आमजन को कोई लाभ नहीं मिल रहा। हारून रंगरेज ने पूछा - ÷जब ज़मीन सरकारी है तो उसमें पहला हक़ गरीब मरीजों और उनके परिवारों का क्यों नहीं माना जा रहा

जनहित में प्रमुख माँगें-

धर्मशाला व कैंटीन की आय-व्यय का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए।

एक स्वतंत्र जांच समिति गठित कर सभी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

यदि लाभ कमाने की मंशा सामने आए तो संचालन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।

बंद पड़ी सरकारी कैंटीन को पुनः शुरू कर गरीब मरीजों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाए।

सरकारी भूमि का उपयोग केवल जनहित में सुनिश्चित किया जाए।

?? धर्मशाला में कोई भी रूम बिना डॉक्टर की अनुमति के न दिया जाए।

÷गरीब की थाली और सिर पर छत - दोनों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे÷ - मोहम्मद हारून रंगरेज

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस विषय में शीघ्र और ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो यह मुद्दा प्रदेश स्तर पर उठाया जाएगा।

ज्ञापन की प्रतिलिपि राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य एवं महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक को भी सौंपी गई है।

कोर्ट से निर्दोष साबित युवक को पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र में दिखाया अपराधी!'

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

शाहपुरा राजेन्द्र खटीक।

भीलवाड़ा (राजस्थान)- भीलवाड़ा जिले के एक युवक ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोर्ट से दोषमुक्त (Acquitted) होने के बावजूद पुलिस उसके चरित्र प्रमाण पत्र में झूठा "Pending Trial" दिखाकर उसका करियर बर्बाद कर रही है।

पीड़ित युवक सुरज कुमार खटीक ने बताया कि वर्ष 2022 में पारिवारिक विवाद के चलते उनके खिलाफ IPC की धारा 323, 341 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो बाद में आपसी समझौते (राजीनामा) के साथ समाप्त हुई और कोर्ट ने उन्हें 12/11/2022 को दोषमुक्त घोषित कर दिया। रिश्वत नहीं दी, इसलिए रिपोर्ट बिगाड़ी सुरज का आरोप सुरज का दावा है कि पुलिस विभाग के एक कर्मचारी जानकीलाल द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी और धमकी दी गई थी कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो चरित्र प्रमाण पत्र में "Pending Trial" दिखाया जाएगा जिससे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

÷मेरे छोटे भाई का वेरीफिकेशन बिना किसी आपत्ति के हो गया जबकि मेरी रिपोर्ट में झूठी जानकारी देकर मेरा भविष्य बर्बाद किया जा रहा है।÷ सुरज खटीक

स्क को दिया गया शिकायत पत्र, अब बयान के लिए बुलाया गया।

सुरज ने 17 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक (स्क) भीलवाड़ा को एक लिखित शिकायत देकर पुलिस रिकॉर्ड सही करने और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है।इस शिकायत के बाद उन्हें थाना स्तर पर बयान देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन पारिवारिक कारणों से वह उपस्थित नहीं हो पाए और उन्होंने लिखित बयान थाने को प्रेषित किया।

न्याय की उम्मीद सुरज ने कहा कि वह सिर्फ इंसाफ चाहता है, और दोषमुक्त होने के बावजूद यदि उसका चरित्र प्रमाण पत्र गलत बना रहा तो यह सिर्फ उसके नहीं बल्कि हर उस युवा के साथ अन्याय है जो ईमानदारी से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है।

युवाओं में आक्रोश, सवाल उठे पुलिस प्रक्रिया पर

इस प्रकरण के सामने आने के बाद कई युवाओं ने पुलिस के चरित्र प्रमाण पत्र प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि कोर्ट से बरी हुए व्यक्ति को भी दोषी मान लिया जाए तो यह न्यायपालिका का अपमान है।

कोटड़ी एनिमल रेस्क्यू टीम के शेल्टर पर सत्संग का आयोजन

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

आकोला (रमेश चंद्र डाड)कोटडी एनिमल रेस्क्यू टीम के शेल्टर पर आज श्री राम सत्संग मंडल ने सत्संग का आयोजन किया इसमें सभी महिलाओं ने भगवान राम का नाम लेते हुए सत्संग किया तथा बीमार गौ वंश को हरा चारा खिलाया !इस अवसर पर सभी माता ने संकल्प किया की समय-समय पर बीमार गौ वंश को देखकर उनसे संबंधित किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन दिया ओर बताया की समय-समय पर इस प्रकार सत्संग का आयोजन इस शेल्टर पर करते रहेंगे ! सभी महिलाओं ने एक कट्ठा बांटे का बीमार गौ वंश के लिये सप्रेम भेंट किया गया जिससे केंद्र पर उपस्थित छोटे-छोटे बच्चों के चेहरे खिल उठे इन बच्चों की टीम काफी वर्षों से बीमार गौ वंश की सेवा करती रहती है इसमें सभी पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं ! श्री राम सत्संग मंडल कोटड़ी की माताओ ने बच्चों के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की! इस अवसर पर आशा मुंदडा, उगम सुवालका, गीता बाई, भंवरी सुथार, रुकमा बाई, शांति देवी सहित महिलाओं का समूह उपस्थित था ओर टीम की ओर से सुनील सेन, राजाराम, अर्पित सेन उपस्थित थे!

शिक्षा, मेडिकल, जागरूकता कैंपों के लिए महिलाएं तैयार रहें -यासमीन महिलाओं की दुश्मन महिला न बने -ठगेला

शाहपुरा राजेन्द्र खटीक।

नोएडा-भारतीय महिला उत्थान समिति की सभा में नोएडा (उ.प्र.) में हुई।अपने अध्यक्षीय भाषण में यास्मीन नाज ने कहा हमें अपनी समिति का रिन्युवल व उसका बैंक अकाउंट खोलना है।उसके बाद शिक्षा कैंप, मेडिकल व नशाबंदी व जागरूकता कैंप सभी के सहयोग से लगाने है।आफिया नाज ने सभी से समिति के कार्यों व उद्देश्यों पर विचार रखने का आग्रह किया।बिलाल ने कहा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम चाहते हैं सभी आय व व्यय बैंक के माध्यम से हो, और बैंक में अकाउंट खोलने के लिए दो तिहाई हस्ताक्षर आवश्यक है।

डा. नेतराम ठगेला, मुख्य सलाहकार ने पुरुषो को भारतीय महिला विकास

समिति में लेने के फैसले की सराहना करते हुए कहा सामान्यतः महिलाओं की विरोधी कोई महिला होती है।उदाहरणार्थ हमारी सचिव नूर आरा एनजीओ चलाती थी स्नातकोत्तर है पीएचडी कर रही थी।शादी के बाद उनकी नौकरी व एनजीओ दोनों उनकी सास ने छुडवा दी।आज इन्हें बच्चे पालने के लिए आशा वर्कर का काम करना पड़ रहा है। नूर आरा ने बताया रामपुर में मेरे एनजीओ ने काफी नाम कमाया, मेरे स्कूल में टीचर के तौर पर सम्मानित होती रही हूंघर बसाने के लिए सबकुछ छोड़ना पड़ा।एक्सीडेंट में पति नहीं रहे, दोहरा बर्ताव की हद है सास व्यापार चला रही है मुझे सरकारी नौकरी भी नहीं करने दी।08 साल का बच्चा है, कुछ तो करना ही है, हम महिला समिति के माध्यम से घर घर जाकर जन जागरण करेंगे व नर और नारी समान है समझाएंगे। इस अवसर पर उपकोषाध्यक्ष नसीम और सदस्य कार्यकारिणी शिवानी झा व नौशाबा ने भी विचार रखे।अंत में जलपान व अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभा सम्पन्न हुई।

संस्थान पदाधिकारियो एवं भक्तों ने विधायक को पांच सूत्रीय विकास का मांग पत्र सौंपा

आकोला (रमेश चंद्र डाड) श्रीबाणमाता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान गोवटा बांध पर विकास के कार्य करवाने के सम्बन्ध में विधायक शर्मा को पदाधिकारियो एवं भक्तों ने पांच सूत्रीय विकास का मांग पत्र सौंपकर शीघ्र कार्यप्रारंभ करवाने की मांग की है। श्री बाणमाता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने नेतृत्व में विधायक गोपाल लाल शर्मा को दिए मांग पत्र में बताया कि बाणमाता शक्तिपीठ मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां प्रत्येक रविवार हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते है। दोनों नवरात्र में नौ दिवसीय महोत्सव में लाखों यात्री आते है। पक्षाघात तथा अन्य असाध्य रोगों का दैवीय कृपा से उपचार होता है। प्रतिदिन सैकड़ों रोगी बाणमाता के यहां रहते है। बाणमाता के यहां विकास के कार्यों की महत्ती आवश्यकता है जिन्हें करवाने की मांग की है।

विधायक शर्मा से फलासिया से बाणमाता के यहां

2 . 5 किलोमीटर (ढाई किमी) की दूरी तक आने जाने के लिए डिवाइडर सहित 7 .5 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता है। अभी सड़क की चौड़ाई कम है जिससे वाहनों की आवाजाही में भारी परेशानी होती है। बाणमाता के यहां नहर के मोड से मन्दिर तक जाने के लिए 1 किलोमीटर बायपास की सड़क बनवाई जाए। इससे नवरात्र महोत्सव , मेले और बड़े आयोजन के समय एक तरफा यातायात हो सकेगा। बाणमाता के यहां निर्मित गोवटा बांध की चादर वाली मुख्य दीवार के नीचे मेनाली नदी में दोनों किनारों पर आधुनिक घाट बनवाए जाए। स्नान के बाद महिलाओं के वस्त्र पहनने के लिए कमरे भी बनवाए जाए। रोगियों के ठहरने एवं सांस्कृतिक आयोजन हो सके जिसके लिए डोम बनाया जाए जिससे सुविधा मिलेगी। बाणमाता गोवटा से खंगार जी का खेड़ा जाने के लिए 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जाए। इससे राहत मिलेगी। जिससे इस क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में पहचान होगी। क्षेत्र की जनता, सभी भक्तजन ऋणी रहेंगे। विधायक प्रतिनिधि मनोज सनाढ्य, पूर्व सरपंच सराना रामप्रसाद जाट, पूर्व सरपंच मोटरों का खेड़ा गणेश जाट, प्रभुनाथ योगी, लादूलाल कुमावत, प्रमोद धाकड़, कन्हैया लाल धाकड़, खाना धाकड़ सहित पदाधिकारी, सदस्यगण, भक्तजन मौजूद थे।

पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

आकोला (रमेश चंद्र डाड) सिंगोली चारभुजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान - एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह रहे। अध्यक्षता पंचायत प्रशासक राकेश कुमार आर्य ने की। विशिष्ट अतिथि अजीत सिंह, राजेंद्र सिंह पुरावत, राधेश्याम सेन और राजेंद्र कुमार मौजूद रहे। विद्यालय परिसर में फूलदार, फलदार और छायादार 50 पौधे लगाए गए। संचालन मथुरा लाल माली ने किया।

बाणमाता शक्तिपीठ गोवटा बांध पर किया पौधरोपण

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

आकोला (रमेश चंद्र डाड) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम अन्तर्गत मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाणमाता शक्तिपीठ गोवटा बांध पर महंत बालकदास महाराज के मार्गदर्शन में पौधरोपण किया गया मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि इस दौरान विधायक गोपाल खंडेलवाल जिला परिषद सदस्य हरि लाल जाट पंचायत समिति सदस्य धनराज जाट पूर्व सरपंच राम प्रसाद जाट विधायक प्रतिनिधि मनोज सनाढ्य बद्रीलाल जाट प्रभु नाथ योगी गणेश जाट रामचंद्र जाट उप सरपंच मोडू लाल सहित अन्य के पौधे लगाए बाणमाता परिसर में 551 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा तथा पानी पिलाने का प्रबन्ध संस्थान कर रहा है

प्रेस सोसायटी शाहपुरा की पूर्व कार्यकारिणी भंग,नवीन कार्यकारिणी का गठन शीघ्र होगा:जिला महासचिव

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

भीलवाड़ा /भीलवाड़ा प्रेस सोसायटी रजिस्टर्ड द्वारा गठित शाहपुरा प्रेस सोसायटी की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है तथा पूर्व में सदस्यता ग्रहण करने वाले कुछ सदस्यों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया था परंतु निरंतर मिल रही पद के दुरुपयोग की शिकायतों के कारण सभी सदस्यों की सदस्यता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है तथा शाहपुरा क्षेत्र के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को इस बाबत अवगत करा दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रेस सोसायटी के नाम से सदस्य या पदाधिकारी होने का दावा करता है तो उसकी जानकारी जिला मुख्यालय स्थित भीलवाड़ा प्रेस सोसायटी को लिखित में दी जा सकती है तथा शीघ्र ही क्रियाशील मर्यादित पत्रकारों को प्रेस सोसायटी की सदस्यता दी जाकर शाहपुरा की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा ।

'धौलपुर पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत'

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

धोलपुर, राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे धौलपुर उनके स्वागत के लिए पचगांव पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीयो ने किया भव्य स्वागत किया खाद आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा धौलपुर में जिला लेवल की बैठक लेने के लिए पधारे हैं धौलपुर के जिला अधिकारियों की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, उनको लेने के लिए जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली, धौलपुर करौली लोकसभा की प्रत्याशी इंदु देवी, धौलपुर के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा की प्रत्याशी नीरज शर्मा, सैंपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल, पूर्व जिलाउपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, जिला महामंत्री नवल लोधा, मदन कोली, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, युवा नेता जयवीर पोसवाल, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, युवा नेता वाचाराम बघेल, डॉ मनोज शर्मा, हरेंद्र राव, युवा मोर्चा संयोजक पुष्पेंद्र राजावत, शिव शंकर परिहार, रविंद्र हथवारी, आनंद शर्मा, रितेश सक्सेना, संदीप शर्मा, पंकज शर्मा, दिलीप पाराशर, दीपूकुशवाहा, राज सिंह, रामकुमार कुशवाहा, संदीप दोपुरा, मनोज परिहार, राम त्रिवेदी, सुभाष गर्ग, दुर्गेश श्रीवास्तव सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे

शाहपुरा बायपास भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का हल्ला बोल - जनता का फूटा आक्रोश!'

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

शाहपुरा शहर में कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज शाहपुरा बायपास मार्ग की बदहाल स्थिति और निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन शाहपुरा उपखंड कार्यालय के समक्ष आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

इस प्रदर्शन का नेतृत्व शाहपुरा-बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार रैगर एवं नगर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश सेन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महावीर कुमावत ने किया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें प्रमुख रूप से उठाई गईं-

1.बायपास मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए,

दोषी ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो,

2.अधूरा निर्माण कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शाहपुरा बायपास अब तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया है, फिर भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है – जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है।

नरेंद्र कुमार रैगर (विधायक प्रत्याशी, कांग्रेस) ने कहा

÷यह केवल टूटी सड़क नहीं है, यह जनता के टूटे हुए विश्वास का प्रतीक है। कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनता को उनका हक दिलवाएगी।÷

रमेश सेन (कार्यवाहक नगर अध्यक्ष, कांग्रेस) ने कहा-

÷भाजपा सरकार की निष्क्रियता और गहराते भ्रष्टाचार ने शाहपुरा की विकास योजनाओं को चौपट कर दिया है। अब जनता चुप नहीं बैठेगी।÷

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ÷भ्रष्टाचार मुक्त शाहपुरा÷ की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता लादूराम चावला अर्जुन सिंह राणावत नंदकिशोर टेलर सत्यनारायण पाठक रामप्रसाद धाकड़ माणक घुसर अजय मेहता प्रदेश सचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ अतुल त्रिपाठी पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष नमन ओझा नेता प्रतिपक्ष रचना सुनील मिश्रा एडवोकेट अनिल शर्मा पहलवान मंसूरी युवा नेता मिंकू पोंडरिक यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह उपाध्यक्ष राम सिंह मीणा मंडल अध्यक्ष हनुमान महावीर बैरवा वैष्णव रामचंद्र बेरवा नगर महामंत्री ओम सिंधी सुनील पाराशर मंडल अध्यक्ष सांवरलाल कुमावत देवरिया सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष जयंती नगर यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन पोंडरिक पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश फमड़ा शिवराज आचार्य यूनुस खान मिट्ठू लाल प्रजापत कुलदीप राजवीर गुर्जर कुलदीप यादव शिवराज रेगर सांवरलाल कुमावत कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने जनाक्रोश को और बल दिया।

द मूवमेंट ऑफ इंडिया
खोजी पत्रकारिता
का तेज बढ़ता अखबार
अब मोबाइल पर भी पढ़िए अखबार
हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करे
+91 96949 57624, 87695 58132, 94136 45605

ब्रिक्स मानों व्हाट्सएप समूह!

जब गोल्डमैन सैक्स ने 2001 में "ब्रिक्स (BRICs)" शब्द गढ़ा था, तब यह कोई ठोस संगठन नहीं था, बस, उभरती अर्थव्यवस्थाओं—ब्राजील, रूस, भारत और चीन—के जमवाड़े का एक कल्पनाशील, आकर्षक संक्षिप्त नाम था। पर दुनिया ने उसे भविष्य की आर्थिक ताक़त के रूप में देखा। लेकिन 2009 तक आते-आते यह शब्द आर्थिकी, आँकड़ों की ताकत का नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रंग लेने लगा। और जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तो ब्रिक्स (BRICS) एक वास्तविक मंच बन गया—पाँच अलग भूगोल, पाँच अलग आवाजें, पर एक साझा ख्याल कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बने जो केवल पश्चिम के इर्द-गिर्द न घूमे। वक़्त भी अनुकूल था। बहुध्रुवीयता (Multipolarity) अब केवल वैकल्पिक कल्पना नहीं थी। पश्चिम, 2008 की आर्थिक मंदी से उबरने की कोशिश में था, चिंता व आत्मनिरीक्षण में खोया हुआ था। वहीं ये नई अर्थव्यवस्थाएँ आत्मविश्वास के साथ मंच पर आ रही थीं—बढ़ती जीडीपी (GDP), तेज होती आवाजें, और वैश्विक निर्णयों में हिस्सेदारी की माँग के साथ। बाते और शब्दावली भव्य थी, तस्वीरें दमदार। ब्रिक्स (BRICS) ने अपनी समिट कैलेंडर तय किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank) जैसी संस्थाएं खड़ी कीं, साझा करेंसी और वैकल्पिक रेटिंग एजेंसी (Rating Agency) जैसे विचारों पर चर्चा की। कुछ वर्षों तक लगा मानो यह समूह सिर्फ बड़ नहीं रहा, बल्कि अपनी एक नयी वैश्विक पहचान बना रहा है। लेकिन अब 2025 तक आते-आते यह तस्वीर धुंधली हो गई है। अब ब्रिक्स (BRICS) ने विस्तार कर ब्रिक्स प्लस (BRICS+) का रूप ले लिया है—11 सदस्य और कई और कतार में खड़े। मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया जैसे नए नाम इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह समूह अब दुनिया की आधे से अधिक आबादी और जी-7 (G7) से अधिक 20 ट्रिलियन डालर अधिक जीडीपी का समूह है। पर नया एक गंभीर सवाल आ खड़ा हुआ है। मुद्दा यह यह नहीं है कि ब्रिक्स (BRICS) कितना बड़ा हुआ है, बल्कि यह है कि क्या वह एकजुट हुआ है? सदस्य देशों के बीच दरारें अब छिपी नहीं हैं। भारत और चीन—दो प्रमुख स्तंभ—अब भी सीमा विवाद में उलझे हैं। रूस का यूक्रेन युद्ध इस समूह की स्थिरता की छवि को झकझोर चुका है। ब्राजील की विदेश नीति सत्ता परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। शासन प्रणाली में भी भिन्नता गहरी है—लोकतांत्रिक भारत और ब्राजील से लेकर निरंकुश चीन और रूस तक। अभी भी इस समूह का कोई साझा व्यापार समझौता नहीं है, न ही कोई एकजुट विदेश नीति या साझा करेंसी। और जिस रेटिंग एजेंसी (Rating Agency) की चर्चा पहले होती थी, वह अब गुम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank) भी अब वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा आंतरिक विरोधाभासों का प्रबंधन करने में व्यस्त है। ब्रिक्स (BRICS), जो कभी एक वैकल्पिक ध्रुव की कल्पना था, आज कई बार एक ऐसा व्हाट्सएप समूह (WhatsApp Group) दिखता है—जहाँ चर्चाएँ तो बहुत हैं, लेकिन तालमेल कम। ब्रिक्स प्लस (BRICS+) में देशों बढ़ी है लेकिन अस्थिरता भी है। मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के शामिल होने से इसकी प्रतिनिधिकता तो बढ़ी है, लेकिन इसके वैचारिक मतभेद भी गहरे हुए हैं। यदि एकमात्र कोई साझा धागा है तो वह पश्चिमी वर्चस्व के प्रति असंतोष, विशेषकर वैश्विक वित्त और प्रतिबंध नीतियों को लेकर। लेकिन असंतोष से परे, सवाल यह है—क्या कोई साझा दृष्टिकोण है? ब्रिक्स (BRICS) के भीतर वैचारिक विविधता विशाल है। रूस जीवाश्म ईंधनों से चिपका है, जबकि मंच पर हरित विकास की बातें होती हैं। यूएई (UAE) चीनी तकनीक में आगे बढ़ रहा है, वहीं सऊदी अरब ब्रिक्स (BRICS) को लेकर सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन पर्दे के पीछे अब भी वॉशिंगटन से जुड़ा रहता है। और चीन—जो हमेशा से इस मंच का सबसे बड़ा, सबसे चुप्पा-शातिर खिलाड़ी रहा है—इस पर अपनी छाया बनाए रखता है। हाल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सम्मेलन में न आना इस चिंता को और बढ़ा गया कि चीन अब इस मंच को किस नज़र से देखने लगा है? फिर भी, तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद, ब्रिक्स (BRICS) अप्रासंगिक नहीं हुआ है। दुसरे विश्व युद्ध के बाद बने पश्चिम-प्रधान वैश्विक ढाँचे—अमेरिकी नेतृत्व, तेल-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था, और मुक्त व्यापार व्यवस्था अब दरक रही हैं। इसी खलीपन में ब्रिक्स (BRICS) को अवसर दिखता है। यह मंच आज ग्लोबल साउथ (Global South) की सबसे प्रमुख आवाज बन चुका है। और अब चुपचाप एक रणनीतिक बदलाव भी हो रहा है—ब्रिक्स (BRICS) देश पश्चिम-नियंत्रित आर्थिक ढाँचों के समानांतर अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। ये डॉलर का कोई तत्काल छोड़ने वाले नहीं नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी वह पुनर्रचना है जो उन अनुभवों से उपजी, जहाँ इन देशों को क्रेडिट इनकार या प्रतिबंध झेलने पड़े। भारत और ईरान जैसे देश अब इस वित्तीय आत्मनिर्भरता को अस्तित्व की रक्षा मानते हैं। भारत के लिए यह संतुलन और भी बारीक व गंभीर है। वह एक ओर ब्रिक्स (BRICS) को ग्लोबल साउथ (Global South) का प्रवक्ता बनाना चाहता है, दूसरी ओर क्वाड (Quad) और आई2यू2 (I2U2) जैसे मंचों में अपनी पश्चिमी साझेदारी को भी बढ़ा रहा है। यह दोहरी रणनीति ब्रिक्स (BRICS) की अंदरूनी दुविधाओं, अंतर्विरोधी बनावट का ही सबूत है। ब्रिक्स प्लस (BRICS+) अब पहले से कहीं अधिक बड़ा, ज़्यादा सुर्खियां, और अधिक विविधतापूर्ण मंच है। लेकिन वह पहले से अधिक बिखरा, और शायद स्वयं को लेकर दुविधा में भी है। यह कभी पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के रूप में देखा गया था, लेकिन अब वही असमानताएँ इसमें भी झलकने लगी हैं। चीन के दबदबे, उसकी छाया से कई तरह की समस्याएं हो गई है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि ब्रिक्स (BRICS) असफल हो गया है। यह आज भी एक ऐसा मंच है जहाँ ग्लोबल साउथ (Global South) की आवाज़ बिना अनुवाद के सुनी जाती है। लेकिन यह कहना कि यह मंच एकीकृत भू-राजनीतिक शक्ति बन चुका है—शायद अभी केवल एक आकांक्षा है। ब्रिक्स (BRICS) अब केवल एक नाम नहीं है—यह अब एक परीक्षा है: क्या महत्वाकांक्षा मतभेदों को पार कर सकती है? क्या देशों की भीड़ बढ़ने से एकता बनी रहेगी? कोई साझा मकसद बनेगा?

-श्रुति व्यास

जवान देश, बुज़ुर्ग सत्ताः सठियाई राजनीति!

पिछले साल जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज थी, तो सबसे ज़्यादा चर्चा नीतियों की नहीं, उम्र की थी। जो बाइडन की याददाश्त को लेकर सवाल थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के भौकाल पर भी। मुद्दा यह नहीं था कि कौन बेहतर नेता है, बल्कि यह कि किस उम्र तक का नेतृत्व स्वीकार्य है? आज वही असहजता भारत की राजनीति में भी हल्के सुरों में सुनाई दे रही है। बंद दरवाजों के पीछे और नपे-तुले शब्दों में यह सवाल आकार ले रहा है—क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब पद छोड़ देना चाहिए, उस 75 साल की अनौपचारिक सीमा का पालन करते हुए, जिसे कभी उन्होंने खुद स्वीकार किया था? बीते हफ्ते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद ये कानाफूसी तेज हुई है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद नेताओं को स्वेच्छा से पीछे हट जाना चाहिए। यह सीधा इशारा नहीं था, लेकिन भारतीय राजनीति में इशारे, बयान से कहीं ज़्यादा गूंजते हैं। यह अंतर्विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं है। अफ्रीकी देश कैमरून में 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया, जो 1980 के दशक से सत्ता में हैं, ने हाल ही में घोषणा की कि वे आठवीं बार चुनाव लड़ेंगे। बहुतों को उम्मीद थी कि वे अब पद छोड़ेंगे—चाहे थकावट के कारण या उम्र के सम्मान में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, उनके इस फैसले ने वहां की युवा आबादी और सत्ता के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। एक ऐसे देश में, जहां 60 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम है और मतदाता का बड़ा हिस्सा 30 से नीचे, वहां बिया की भाषा और सोच अब युवा पीढ़ी के लिए अपरिचित और असंबंधित लगने लगी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि युवा मतदाता आगे मतदान से दूर रह सकते हैं—निराश, कटे हुए, और दोहराव से थके हुए। समय और नेतृत्व के बीच यह खिंचाव अब वैश्विक विमर्श में कई तरफ है। हम उस युग में रह रहे हैं, जहां दुनिया एआई क्रांति में है, सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत तेज हैं, और जलवायु से लेकर रोजगार तक के मुद्दों पर युवाओं की अगुवाई में आंदोलन चल रहे हैं। और फिर भी, दुनिया के ज़्यादातर राजनीतिक ताने-बाने, चेहरे बीसवीं सदी में ही जमे हुए हैं। भारत में यह विरोधाभास और गहरा है। भारत की 140 करोड लोगों की आबादी की औसत आयु 30 वर्ष से भी कम है, लेकिन नेतृत्व अब भी 70 पार के लोगों के हाथ में है। ऐसे में सवाल उठता है—क्या राजनीतिक कल्पना, भविष्य की दृष्टि पिछली सदी के फ्रेम, जुमलों, भाषणों में ही फंसी रहेगी? प्राचीन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कभी कहा था कि उम्र अनुभव और गहराई देती है, लेकिन इसके साथ बदलाव से जड़ता भी आती है। सत्ता, उन्होंने चेताया था, इंसान के चरित्र की अच्छाई और बुराई दोनों को बढ़ा देती है। आज अगर दुनिया पर नजर डालें—बेंजामिन नेतन्याहू 74 के हैं, पुतिन और शी जिनपिंग दोनों 71, ईरान के अयातुल्ला खामेनेई 85, और पाकिस्तान के शहबाज़ शरीफ 73 साल के। क्या उम्र ने इन्हें अधिक शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण, समझदार नेता बनाया है, या केवल सत्ता से चिपके रहने की जिद बनवाई है? प्लूटार्क ने यह भी कहा था कि किसी समाज को अपने बुज़ुर्गों को पूरी तरह छोड़ नहीं देना चाहिए—क्योंकि महत्वाकांक्षा जब विवेक से अलग हो जाए, तो वह खतरनाक हो जाती है। लेकिन आज का समय ऐसे उदाहरणों से भी भरा है जहाँ युवाओं ने नेतृत्व संभाला—आयरलैंड के लियो वराडकर 38 की उम्र में प्रधानमंत्री बने; न्यूजीलैंड की जैसिंडा आर्डर्न 37 की उम्र में; फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों 39 की उम्र में राष्ट्रपति बने। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वराडकर और आर्डर्न ने खुद सत्ता से संन्यास लिया—बिना हार, बिना दबाव, केवल इसलिए कि वे अब भीतर से तैयार नहीं थे। जैसिंडा ने प्रधानमंत्री पद छोड़ते हुए कहा था, "अब मेरे पास उतनी ऊर्जा नहीं बची कि इस पद का पूरा न्याय कर सकूं।" सोचे, आज की सत्ता-लोलुप राजनीति में एक नेता की ऐसी स्वीकारोक्ति और उस आधार पर रिटायर होना कितना दुर्लभ है। बावजूद इसके राजनीति लगातार "बुजुर्गतंत्र" से संचालित हो रही है। भारत जैसे देश में, जहां युवा हर क्षेत्र में आगे हैं, वहीं नेतृत्व दो या तीन पीढ़ी पुराने नेताओं के हाथ में है। अमेरिका में, उम्र को लेकर चिंता के बावजूद, करोड़ों लोग अब भी बाइडन और ट्रंप जैसे 70–80 पार नेताओं को चुनने को तैयार हैं। कैमरून में 92 वर्षीय नेता आठवीं बार मैदान में उतर रहे हैं। तो सवाल है—दुनिया की सबसे युवा जनता बार-बार सबसे बुढे नेताओं को क्यों चुन रही है? इसका एक उत्तर कल्पनाशीलता के संकट में छिपा है। लोग विकल्प की कल्पना करने, साहस से कतराते हैं। चारों ओर जो निराशा और व्यवस्था पर विश्वास की कमी है, उसने सोच को कुंद कर दिया है। यह ऐसा है जैसे धुंध ने आकाश ढक दिया हो—और अब उस पार देखना, अंधेरे की खाई में झांकने जैसा लगता है। सोशल मीडिया ने इसे और गहरा किया है। भारत में देखिए—व्हाट्सएप पर मोदी को दैविक नेता की तरह दिखाया जाता है। X (ट्विटर) पर स्थिरता के आंकड़ों की बाढ़ है। इंस्टाग्राम पर 'मोदी है तो मुमकिन है', और राहुल गांधी अब भी 'पप्पू' के फ्रेम से बाहर नहीं आ पाए। तभी जो राजनीतिक संस्थाएं बदलाव के लिए बनी थीं, वे अब इस तरह ढल चुकी हैं कि स्थायित्व को प्राथमिकता दी जाती है। बुढ़े नेताओं के पास पहचान है, नेटवर्क है, और "परीक्षित" होने की छवि है—भले ही थक चुके हों। वहीं दूसरी ओर, राजनीतिक दल भी युवाओं के लिए सशक्त विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। और जिन समाजों में उम्र को अब भी अनुभव और अधिकार का पर्याय माना जाता है, वहां यह चक्र चलता रहता है। Gen Z भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बदलाव की आवाज़ बुलंद कर रहा हो, लेकिन चुनावों में अक्सर 'परिचित' और 'स्थिर' विकल्प को ही वोट देता हैं। आज डर यह नहीं है कि युवा तेजी से आगे आ जाएंगे—डर यह है कि सत्ता में जमे बुजुर्ग, 'स्थिरता' के नाम पर, संस्थाओं को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो समस्या केवल बुजुर्गतंत्र नहीं है। समस्या उन विचारों की है जो इसे टिकाए रखते हैं—यह धारणा कि केवल बुजुर्ग ही जिम्मेदार शासन दे सकते हैं; कि बदलाव खतरनाक है; विकल्प नहीं है, कि व्यवस्थाएं धीरे चलनी चाहिए जबकि दुनिया चारों ओर तेजी से बदल रही हो और आवश्यकता भविष्य के तकाजे में नए खून की है। जब तक ऐसा नेतृत्व सामने नहीं आता, जो केवल युवा दिखता ही नहीं बल्कि युवा सोचता भी हो—जो समावेशन, कल्पना और तात्कालिकता की भाषा बोले—तब तक भविष्य केवल दरवाज़ा खटखटाता रहेगा उन दरवाजों पर, जो एक दिन इतने बूढ़े हो जाएंगे कि उस दस्तक को सुन ही नहीं पाएंगे।

-श्रुति व्यास

आधार का अब क्या होगा!

देश के 99.9 फीसदी लोगों को मिले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और आधार कार्ड का अब क्या होगा? यह लाख टके का सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे तो यह सवाल बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने के बाद से ही पूछा जा रहा है लेकिन अब ज्यादा प्रासंगिक हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इसकी उपयोगिता को शून्य कर दिया है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मसले पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक हलफनामा देने को कहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी थी कि आयोग को मतदाता सूची के सत्यापन में आधार, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने 21 जुलाई को हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा कि किसी को भी मतदाता बनाने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग उसकी नागरिकता का सत्यापन करे, जो आधार के जरिए नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग ने लिख करके बता दिया कि आधार की कोई उपयोगिता नहीं है। ध्यान रहे केंद्र सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के लिए राज्य की सारी ताकत लगाई थी। सरकार ने इतना दबाव बनाया था कि नागरिक समूहों को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने सितंबर 2018 में आम लोगों को राहत देते हुए कहा कि सरकार किसी भी सेवा के लिए आधार अनिवार्य नहीं कर सकती है। इसके बावजूद सरकार नहीं मानी और उसने नागरिकों पर दबाव बनाए रखा। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी नागरिकों को कई किस्म की सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रही। भले सेवाएं रोकी नहीं गईं, लेकिन यह दबाव बनाए रखा गया कि नागरिक आधार बनवाएं और उसे अपने बैंक खातों से जुड़वाएं, आईटी रिटर्न के अपने खाते से जुड़वाएं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और जमीन खरीद के दस्तावेजों में आधार नंबर लिखवाएं, कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड के साथ जुड़वाएं और यहां तक कि वोटर आईडी के साथ भी आधार जुड़वाने का दबाव बनाए रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने करीब 66 करोड़ मतदाताओं का आधार हासिल कर लिया। सोचें, चुनाव आयोग ने देश के मतदाताओं की गर्दन पर तलवार रख दी कि उन्हें हर हाल में अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अपने इपिक नंबर के साथ यानी आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करना है। आयोग के निर्देश में बहुत साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक नहीं करता है तो उसे इसका वाजिब कारण बताना होगा और चुनाव आयोग को संतुष्ट करना होगा। जाहिर चुनाव आयोग किसी भी कारण से संतुष्ट नहीं हो सकता था। जिस चुनाव आयोग ने सारी आपत्तियों को खारिज करके आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने का अभियान चलाया वह अब कह रहा है कि आधार किसी काम नहीं है! आधार को वोटर आई कार्ड से जोड़ने का विरोध करने वाले लोग सबसे बड़ा कारण बता रहे थे कि उनकी निजता का हनन होगा क्योंकि आधार के साथ बायोमीट्रिक डिटेल्स यानी नागरिकों की उंगलियों के निशाना और आंखों की रेटिना का स्कैन होता है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि उसके पास डेटा प्रोटेक्शन का बेहतरीन सिस्टम है और किसी का डेटा लीक नहीं होगा। कुछ समय पहले तक चुनाव आयोग हर हाल में आधार और मतदाता सूची को लिंक कराने का अभियान चला रहा था उसने अब कह दिया है कि आधार से मतदाता सूची नहीं बनाई जाएगी। ग़ानी अगर किसी के पास पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज आधार है वह मतदाता नहीं बन पाएगा। चुनाव आयोग ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आधार से न तो आवास का पता प्रमाणित होता है, न जन्म की तारीख प्रमाणित होती है और न उससे नागरिकता प्रमाणित होती है। इसका मतलब है कि आधार से सिर्फ यह प्रमाणित होता है कि आप इंसान हैं, एलियन या पशु नहीं हैं। वैसे भी आधार बनाने की प्रक्रिया बहुत ढीली ढाली थी। विधायकों और पार्षदों के लिख कर दे देने से आधार बन जाता था। बिहार के कई जिलों में आबादी से ज्यादा आधार बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार और चुनाव आयोग को यह पता नहीं है। फिर भी कुछ दिन पहले तक आधार को हर पहचान और हर सेवा के लिए जरूरी बताया जा रहा था और अब उसकी उपयोगिता शून्य कर दी गई है। सभी नागरिकों के बैंक खातों को आधार से लिंक किया गया है और सरकार की ओर से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए नागरिकों को मिलने वाली हर योजना का पैसा आधार से लिंक्ड खातों में ट्रांसफर होता है। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र और राज्यों का मिला कर कुल 44 लाख करोड़ रुपए की राशि या सेवा देश के नागरिकों को आधार से जुड़े खातों के जरिए दी जाती है। प्रधानमंत्री सौ बार दावा कर चुके हैं कि जनधन खाता, आधार और मोबाइल यानी जैम के जरिए लाखों करोड़ रुपए की बचत की गई है। ये सारे दावे आधार का महत्व बताने के लिए किए गए। आधार को जीवन का आधार बना दिया गया। हजारों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए। देश के नागरिकों को करोड़ों घंटे इसे बनवाने में लगे। और अब स्थिति यह है कि इससे न तो किसी नागरिक का पता प्रमाणित होगा, न जन्मतिथि प्रमाणित होगी और न उसकी नागरिकता प्रमाणित होगी। क्या यह पूरी तरह से बेकार दस्तावेज हो गया? क्या अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार नहीं मान्य होगा? बैंक खाते खुलवाने या फोन का कनेक्शन लेने के लिए इसे नहीं स्वीकार किया जाएगा? बैंक खातों या आईटी रिटर्न के साथ आधार को लिंक करना अब जरूरी नहीं रह जाएगा? आयुष्मान भारत से लेकर किसान सम्मान निधि तक क्या जितनी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं उनके लिए आधार की बजाय किसी दूसरे दस्तावेज की जरुरत होगी और उसके लिए क्या लोगों को नए सिरे से अपने खातों की केवाईसी दूसरे दस्तावेजों के जरिए करानी होगी? अगर ऐसा होता है तो यह आम लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल वाली बात होगी क्योंकि देश के ज्यादातर लोगों के पास आधार के जरिए बने दस्तावेजों के अलावा दूसरे दस्तावेज नहीं हैं। मैट्रिक पास होने का प्रमाणपत्र या जन्म का और आवास का प्रमाणपत्र या सरकारी नौकरी का प्रमाणपत्र कितने लोग दे पाएंगे?

धर्म, संस्कृति, परंपरा व सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम!

पवित्र श्रावण मास चल रहा है, इस मास में देश के विभिन्न हिस्सों में शिवभक्त देवाधिदेव भगवान महादेव के ऊपर पवित्र नदियों का जल चढ़ाने के लिए सदियों से कांवड़ लेकर आते हैं। हालांकि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि आखिर यह कांवड़ यात्रा क्या है, उन्होंने बेहद सरल शब्दों में यह समझना चाहिए कि कांवड़ यात्रा सनातन धर्मियों की केवल आस्था का ही नहीं बल्कि हमारे प्यारे देश भारत की समृद्धशाली धर्म-सांस्कृतिक, प्राचीन परंपरा और विरासत का एक अद्भुत प्रतीक है। वैसे भी सनातन धर्म-संस्कृति में पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि को देवाधिदेव भगवान महादेव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसलिए शिव भक्तों के द्वारा श्रावण मास की शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा-अर्चना करके कांवड़ से लाये पवित्र जल के माध्यम से जलाभिषेक करके इसको एक भव्य महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पूरे श्रावण मास में ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त दूर-दूर से पवित्र नदियों खासतौर पर गंगा के जल को सनातन धर्म की बेहद प्राचीन धर्म-संस्कृति व परंपराओं के अनुसार लाकर भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। देश-दुनिया में पवित्र नदियों के जल को शिव भक्तों के कंधे पर बांस की बनी कांवड़ के दोनों सिरों पर लटके हुए कलश में लेकर के आने की इस अद्भुत यात्रा को ही कांवड़ यात्रा कहते हैं। सदियों के बाद आज के दौर में शिव भक्त हर वर्ष तरह-तरह की कांवड़ लेकर आते हैं, जो लोगों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र ही नहीं है, बल्कि यह यात्रा प्राचीन धर्म-संस्कृति, परंपराओं व सामाजिक समरसता का एक विशाल अद्भुत संगम है। भगवान शिव के आशिर्वाद से हर वर्ष ही कांवड़ यात्रा से जहां एक तरफ तो लाखों लोगों को रोजगार मिलने से उनका परिवार पलता है, वहीं दूसरी तरफ यह भगवान शिव की पूजा-अर्चना करके उन्हें खुश करने का एक बड़ा अवसर भक्तों को मिलता है। कांवड़ यात्रा लोगों को एक जुट रहकर के जल की एक-एक बूंद की अहमियत को बताते हुए प्रकृति की पूजा के बारे में बताती है, वहीं सनातन धर्मियों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके जातियों के जहरीले बंधनों को तोड़कर के सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है। कांवड़ यात्रा एक कठिन तपस्या भी है, जिसमें भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाते हैं। पवित्र नदियों का जल लेकर के भगवान शिव पर जल चढ़ाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। यहां तक की हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी कांवड़ यात्रा से संबंधित तथ्य मिलते हैं। शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ अलग-अलग तरह की कांवड़ लेकर आते हैं। बहुत सारे भक्त सामान्य कांवड़ लेकर पैदल चलते हैं जिसमें आवश्यकताओं अनुसार भक्त विश्राम करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लाते हैं। वहीं डाक कांवड़ में शिवभक्त गंगा जल लेकर लगातार दौड़ लगाने की कठिन तपस्या करते हुए, शिव-शंभु का जलाभिषेक करते हैं, यह कांवड़ आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। वहीं खड़ी कांवड़ में कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है, विश्राम करते समय भी दूसरा साथी कांवड़ कंधों पर रखता है। वहीं कुछ शिव भक्त बैठी कांवड़ लेकर आते जिसमें वह कांवड़ पास रखकर के बैठकर आराम कर सकते हैं। वहीं कुछ भक्त दंडी कांवड़ लेकर आते हैं जो सबसे कठिन होती है, इसमें कांवड़िया दंडवत प्रणाम करते हुए निशान लगाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, यह सबसे कठिन प्रकार की कांवड़ यात्रा होती है। सदियों पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसके संदर्भ में कई पौराणिक मान्यताएं हैं, माना जाता है कि समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने जब पीकर अपने कंठ में इकट्ठा कर लिया था, तो देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया था। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के मतानुसार रावण को ही पहला कांवड़िया माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर जब ताप से बेहद व्याकुल हो गए थे, तब उन्होंने अपने अन्नय भक्त लंका नरेश रावण को पुकारा था, शिव भक्त रावण ने तत्काल उपस्थित होकर भगवान शिव के हालात देखकर के उनका जलाभिषेक करना शुरू कर दिया था। जिससे भगवान शिव को शांति मिली थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा से जल लाकर के जब पुरा महादेव मंदिर बागपत में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, तब से ही कांवड़ यात्रा की शुरूआत हुई है। वहीं रामायण में उल्लेख मिलता है कि त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने अपने नेत्रहीन माता-पिता को बांस की डंडे के दोनों ओर बंधी टोकरियों में बैठाकर गंगा स्नान व तीर्थाटन करवाने की यात्रा शुरू की थी, तब से ही कांवड़ यात्रा की शुरूआत हुई। हांलांकि आज भी कांवड़ यात्रा में चंद विधर्मी हुड़दंगियों को छोड़ दिया जाए तो यह एक बहुत ही कठिन जप-तप वाली तपस्या है, जोकि शिव भक्त कांवड़ियों के अपने आराध्य भगवान शिव पर अटूट विश्वास के दम पर ही पूर्ण होती है। शिव भक्तों की कांवड़ भगवान शिव के प्रति आस्था अटूट समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को कंधे पर रखकर के पैदल चलते हुए शिव भक्त तरह-तरह के शारीरिक कष्ट सहते हैं, फिर भी शिव भक्तों की भगवान शिव के प्रति आस्था जरा सी भी कम नहीं होती है।

- दीपक कुमार त्यागी

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक दयाराम दिव्य द्वारा मुद्रक वेदांत प्रभाकर, मेधा कम्प्यूटर्स एंड ऑफसेट प्रिंटर्स, ऑफिस नं. 128, वार्ड नं. 25, नंदभवन कांवाखेड़ा पार्क के पास, भीलवाड़ा 311001 (राज.) से मुद्रित एवं एस-20, प्रतापनगर, भीलवाड़ा (राज.) से प्रकाशित। संपादक दयाराम दिव्य 96949 57624, 87695 58132 * PRB एक्ट के तहत ख़बरों के चयन के लिए उत्तरदायी। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भीलवाड़ा होगा